PM-VBRY का पहला बड़ा वितरण: ₹2,400 करोड़, 70 लाख नौकरियाँ

रोजगार-नीति और सामाजिक सुरक्षा | समाचार संदर्भ: 19 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

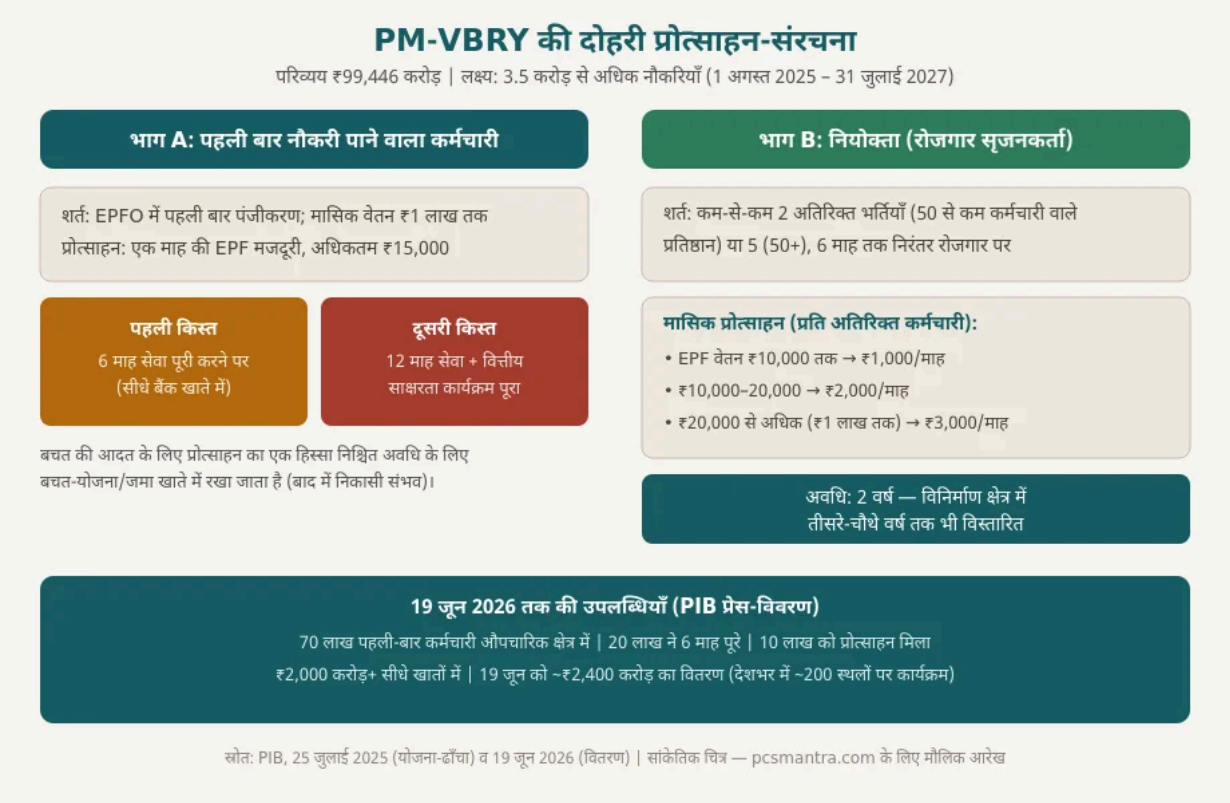
भारत की रोजगार-समस्या की असली गांठ दोहरी है: नौकरियाँ भी कम हैं, और जो हैं उनमें से अधिकतर अनौपचारिक — बिना सामाजिक सुरक्षा, बिना पीएफ-पेंशन की। दशकों से नीति का ज़ोर 'आपूर्ति-पक्ष' (supply side) पर रहा — युवाओं को कौशल दो, नौकरी खुद मिल जाएगी। लेकिन कौशल-प्रमाणपत्र नौकरी की गारंटी नहीं बनता; असली बाधा अक्सर मांग-पक्ष में होती है — नियोक्ता नई भर्ती से क्यों कतराता है? इसी सवाल का उत्तर है 'रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन' (Employment Linked Incentive, ELI): सरकार सीधे उस निर्णय पर पैसा लगाती है जिस पर नौकरी बनती है — नई भर्ती। इसी विचार से कैबिनेट-स्वीकृत ELI योजना 1 अगस्त 2025 से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) के नाम से लागू हुई — ₹99,446 करोड़ के परिव्यय और 2 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के लक्ष्य के साथ। 19 जून 2026 को इस योजना का पहला बड़ा राष्ट्रीय-स्तरीय प्रोत्साहन-वितरण हुआ।

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में PM-VBRY के अंतर्गत लगभग ₹2,400 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए; देशभर में लगभग 200 स्थलों पर साथ-साथ कार्यक्रम हुए (PIB, 19 जून 2026)। PIB के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 से अब तक योजना के तहत 70 लाख पहली-बार कर्मचारी औपचारिक श्रम-बल में जुड़े हैं, प्रोत्साहन 15 लाख से अधिक लाभार्थियों के रोजगार को सहारा दे चुका है, करीब 20 लाख युवा पहली नौकरी में 6 माह पूरे कर चुके हैं, लगभग 10 लाख लाभार्थियों को इस मील-पत्थर पर प्रोत्साहन मिल चुका है और ₹2,000 करोड़ से अधिक सीधे खातों में पहुँचा है। प्रधानमंत्री ने योजना की विशेषता बताई: 'अधिकांश योजनाएँ या तो कर्मचारी पर केंद्रित होती हैं या नियोक्ता पर — यह कार्यक्रम दोनों को साथ समर्थन देता है'; उन्होंने इसे 'युवा और उद्योग के बीच सेतु' कहा।

प्रमुख अवधारणा: रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) क्या है?

पारंपरिक रोजगार-नीति के दो हथियार रहे हैं — कौशल-प्रशिक्षण (आपूर्ति बढ़ाना) और सीधी सरकारी नौकरी/गारंटी (मांग बनाना)। ELI तीसरा हथियार है: निजी क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन, बशर्ते नौकरी 'नई' और 'औपचारिक' (EPFO-पंजीकृत) हो। तर्क सरल है: नियोक्ता के लिए नई भर्ती की सीमांत लागत घटती है (सरकार वेतन का हिस्सा वहन करती है), और कर्मचारी के लिए पहली नौकरी में टिके रहने का नकद प्रोत्साहन बनता है। शर्त EPFO-पंजीकरण रखकर नौकरी-सृजन को औपचारिकीकरण से जोड़ दिया गया है — एक ही प्रोत्साहन से दो नीतिगत लक्ष्य।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

घटना	**PM-VBRY के अंतर्गत ~₹2,400 करोड़ का प्रोत्साहन-वितरण — विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 19 जून 2026; देशभर में ~200 समवर्ती कार्यक्रम (PIB)**
योजना-ढाँचा	ELI योजना → PM-VBRY, प्रभावी 1 अगस्त 2025; परिव्यय ₹99,446 करोड़; लक्ष्य 3.5 करोड़+ नौकरियाँ (2 वर्ष); 1.92 करोड़ पहली-बार कर्मचारी; लाभ-अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियाँ (PIB, 25 जुलाई 2025)
भाग A (कर्मचारी)	EPFO में पहली बार पंजीकृत, वेतन ₹1 लाख/माह तक — एक माह की EPF मजदूरी, अधिकतम ₹15,000, दो किस्तों में: पहली 6 माह सेवा पर, दूसरी 12 माह + वित्तीय-साक्षरता कार्यक्रम पर; कुछ हिस्सा बचत-योजना में निश्चित अवधि के लिए
भाग B (नियोक्ता)	अतिरिक्त भर्ती पर (50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान: कम-से-कम 2; 50+: कम-से-कम 5; 6 माह निरंतर रोजगार) — EPF वेतन-स्लैब के अनुसार ₹1,000/₹2,000/₹3,000 प्रति माह, 2 वर्ष तक; विनिर्माण में तीसरे-चौथे वर्ष तक विस्तारित
प्रगति (19 जून 2026)	70 लाख पहली-बार कर्मचारी औपचारिक श्रम-बल में; 20 लाख ने 6 माह पूरे; 10 लाख को प्रोत्साहन; ₹2,000 करोड़+ सीधे खातों में; प्रोत्साहन 15 लाख+ लाभार्थियों के रोजगार को सहारा (PIB)

दोहरी संरचना कैसे काम करती है — मांग और आपूर्ति दोनों ओर

नियोक्ता-पक्ष (मांग): भर्ती का फैसला लागत-लाभ पर टिकता है। ₹3,000/माह तक का प्रोत्साहन नए कर्मचारी की सीमांत लागत घटाता है — विशेष रूप से कम-वेतन स्लैब में, जहाँ ₹1,000/माह भी वेतन का 10% तक हो सकता है। न्यूनतम अतिरिक्त-

भर्ती शर्त (2 या 5) इसे 'बिज़नेस-एज़-यूज़ुअल' वेतन-सब्सिडी बनने से रोकती है — प्रोत्साहन सिर्फ 'अतिरिक्त' नौकरी पर

कर्मचारी-पक्ष (आपूर्ति/अवधारणा): पहली नौकरी छोड़ने की दर सबसे ऊँची होती है। 6 माह और 12 माह की किस्तें 'टिके रहने' को नकद पुरस्कार देती हैं; वित्तीय-साक्षरता शर्त और बचत-योजना में कुछ हिस्सा रखना — ये डिज़ाइन प्रोत्साहन को खर्च नहीं, संपत्ति-निर्माण बनाते हैं

औपचारिकीकरण-कड़ी: दोनों भागों की दहलीज़ EPFO-पंजीकरण है। अर्थात हर प्रोत्साहित नौकरी सामाजिक-सुरक्षा जाल (पीएफ, पेंशन, बीमा) में भी जुड़ती है — 70 लाख नए EPF-पंजीकरण इसी कड़ी के परिणाम हैं

विनिर्माण-वरीयता: सामान्य क्षेत्र में प्रोत्साहन 2 वर्ष, पर विनिर्माण में 3-4 वर्ष तक — उत्पादन-आधारित रोजगार को गहरा और दीर्घ समर्थन; यह 'मेक इन इंडिया' जैसी औद्योगिक प्राथमिकताओं से मेल खाता है (PIB, 25 जुलाई 2025)

योजना का महत्त्व

नीति-दिशा में परिवर्तन: कौशल-केंद्रीय आपूर्ति-नीति से नौकरी-सृजन-केंद्रीय मांग-नीति की ओर स्पष्ट विस्तार — रोजगार-निर्माण अब सीधे वित्तीय प्रोत्साहन का विषय

पहली-नौकरी अर्थव्यवस्था: 1.92 करोड़ पहली-बार कर्मचारियों का लक्ष्य युवा-आबादीक लाभांश (demographic dividend) को औपचारिक अर्थव्यवस्था में जोड़ने का प्रयास

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: EPFO-शर्त के कारण हर नई नौकरी पेंशन-बीमा के घेरे में — दीर्घकाल में इसका औपचारिकीकरण-प्रभाव प्रोत्साहन-लागत से बड़ा हो सकता है

चुनौतियाँ और प्रश्न-चिह्न

अतिरिक्तता का सत्यापन: प्रोत्साहन 'अतिरिक्त' भर्ती पर है — पर क्या ये नौकरियाँ बिना प्रोत्साहन के भी बन जातीं (deadweight loss)? EPFO-आंकड़े प्रवाह मापते हैं, कारण-संबंध नहीं; वास्तविक मूल्यांकन स्वतंत्र अध्ययन माँगता है (विश्लेषणात्मक)

रोजगार की गुणवत्ता: छह-माह का मील-पत्थर किस्त दिला देता है, पर स्थायी, वृद्धिशील रोजगार नहीं — योजना की असली परीक्षा 2027 के बाद नौकरियों का टिकना होगा (विश्लेषणात्मक)

छोटे प्रतिष्ठानों की पहुँच: EPFO-दस्तावेज़ीकरण, आवेदन-प्रक्रिया और प्रवाह-समय छोटे नियोक्ताओं के लिए बोझ बन सकते हैं — जहाँ रोजगार-क्षमता सबसे अधिक है (विश्लेषणात्मक)

आगे की राह

तीन दिशाएँ निर्णायक होंगी: (i) गुणवत्ता-मूल्यांकन — 12-24 माह के अवधारण (retention) और वेतन-वृद्धि के आंकड़े प्रकाशित हों, ताकि 'बनी' नौकरियों का 'टिकना' भी नीति-मानदंड बने; (ii) सरलीकरण — लघु प्रतिष्ठानों के लिए आवेदन और भुगतान-चक्र सरल हो; (iii) संयोजन — कौशल-योजनाओं (आपूर्ति) और PM-VBRY (मांग) का समन्वित संचालन, ताकि प्रशिक्षित युवा प्रोत्साहित नौकरी तक पहुँचे। 2027 की अवधि-सीमा के बाद विस्तार-निर्णय इन्हीं आंकड़ों पर टिकेगा।

अवधारणा में अंतर

आपूर्ति-पक्ष नीति (कौशल-प्रशिक्षण — कर्मचारी की क्षमता बढ़ाना; नौकरी की गारंटी नहीं) बनाम मांग-पक्ष नीति (PM-VBRY — नई, औपचारिक नौकरी बनने पर ही प्रोत्साहन; क्षमता-सृजन नहीं)। दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हैं: कौशल-योजना युवा को 'नौकरी-योग्य' बनाती है, PM-VBRY नियोक्ता को 'नौकरी देने योग्य'। तीसरा अंतर: रोजगार-गारंटी योजनाएँ (जैसे ग्रामीण रोजगार-ढांचा) सीधी सार्वजनिक रोजगारी देती हैं, जबकि PM-VBRY निजी-क्षेत्र नौकरी-सृजन को प्रोत्साहित करता है।

मेंस दृष्टि

GS-III: रोजगार, औपचारिकीकरण, विनिर्माण-नीति; GS-II: सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी डिलीवरी (DBT)। उत्तर में योजना-तथ्य (₹99,446 करोड़, 3.5 करोड़ लक्ष्य, भाग A/B, 19 जून 2026 के आंकड़े — PIB attributed) और मांग-आपूर्ति का विश्लेषणात्मक ढाँचा रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ श्रम-बाजार में मांग-पक्ष की कमी दूर करने का प्रयास हैं।' PM-VBRY की संरचना और प्रारंभिक परिणामों के आलोक में टिप्पणी कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: रोजगार-समस्या की दोहरी गांठ।

मुख्य भाग में: अवधारणा: ELI और मांग-पक्ष तर्क; संरचना: भाग A/B, EPFO-कड़ी, विनिर्माण-वरीयता; परिणाम: 19 जून 2026 के आंकड़े; चुनौतियाँ: अतिरिक्तता, गुणवत्ता, पहुँच; मार्ग: मूल्यांकन, सरलीकरण, कौशल-संयोजन।

निष्कर्ष में: प्रोत्साहन-वितरण और EPFO में नए पंजीकरण को योजना से उत्पन्न शुद्ध अतिरिक्त नौकरियों का प्रमाण न मानें; रोजगार टिकने, वेतन और छोटे प्रतिष्ठानों की पहुँच का मूल्यांकन सुझाते हुए कर्मचारी तथा नियोक्ता समर्थन को कौशल-प्रशिक्षण का पूरक रखें।

स्रोत

- PIB — PM-VBRY प्रोत्साहन-वितरण विवरण (19 जून 2026)
- प्रधानमंत्री कार्यालय — वितरण कार्यक्रम विवरण (19 जून 2026)
- PIB — PM-VBRY योजना-ढाँचा और प्रारंभ विवरण (25 जुलाई 2025)

योजना-ढाँचा (परिव्यय, लक्ष्य, भाग A/B की शर्तें) PIB के 25 जुलाई 2025 विवरण से; 19 जून 2026 के प्रगति-आंकड़े PIB/pmindia विवरण से — सभी शब्दशः सत्यापित।

यह भी पढ़ें: कौशल विकास: प्रशिक्षण की समस्या (आपूर्ति-पक्ष की समझ) | EPFO की ₹25,000 वेतन-सीमा: व्यापक सामाजिक सुरक्षा की ओर।

याद रखें: PM-VBRY की खासियत युग्मन है — नौकरी बनेगी तभी प्रोत्साहन मिलेगा, और हर प्रोत्साहित नौकरी औपचारिक होगी। पहले वर्ष के आंकड़े (70 लाख नए पंजीकरण) उत्साह देते हैं; असली परीक्षा ये नौकरियाँ कितनी टिकती हैं, वह 2027 के

बाद सामने आएगी।